	Schemes	Plan allocation during 1966-67 (Rs. Crores)
1.	B.H.E.L., Hardwar	32.00 (for all BHEL Projects including Tiruchi and Hyderabad).
2.	Triveni Structurals	1.00
3.	Pumps & Compressors	0.50
4.	Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Rishikesh	8.00
5.	Fertilizer Factory, Gorakhpur	9.98

Out of the above projects the Drugs and Pharmaceuticals factory at Rishikesh was completed during 1966-67.

Handloom Industry in U.P.

7439. SHRI VISHWA NATH PANDEY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the quantity of yarn consumed by the Handloom Industry in Uttar Pradesh during 1966-67 ; and

(b) the amount provided to each Weavers' Cooperative Society in the form of loans and grants during the above period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) 32.5 million Kilograms.

(b) The Central Government provides assistance in the form of loans and grants to the State Government and the latter likewise gives assistance to Weavers' Co-operative Societies. The Central Government have no information on the amount of loans and grants given to each Weavers' Cooperative Society.

Quota of Iron and Steel allotted to U.P.

7440. SHRI VISHWA NATH PANDEY: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) the quality and quantities of iron and steel quota allotted to Uttar Pradesh in 1967-68 and the quantity actually dispatched ;

(b) whether it is a fact that the aforesaid materials were not supplied to the Small Scale Industries Corporation of Uttar Pradesh ;

(c) whether it adversely affected the Industries based on these materials ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to improve the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) to (d) The material is being collected and will be placed on the Table of the House.

Five-Year Strike Moratorium in Public Sector Steel Plants

7441. SHRI NAMBIAR :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether in his Press Conference on the 20th March, 1968 he suggested 5-year strike moratorium in the public sector steel plants ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) : (a) and (b). In the background of unsatisfactory industrial relations in the steel plants under Hindustan Steel Ltd. during the year 1967-68 and, in particular, at Durgapur and Rourkela Steel Plants, discussions have been held with certain Central Trade Unions with a view to having an arrangement by which a truly representative union could be recognised in each of the steel plants as the sole bargaining agent empowered to negotiate collective and general issues with the management and the establishment of a machinery of Joint Standing Committees for securing settlement of industrial disputes by negotiations, conciliations etc. In this context, it has also

been suggested that if the proposal to have one recognised union for one steel plant is accepted, there could be a long term agreement—say for five years—providing for automatic settlement of industrial disputes without resort to strikes etc. These discussions are still continuing.

उत्तर प्रदेश के लिये धातुओं का नियतन

7442. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम, उत्तर प्रदेश के लिये प्रति वर्ष प्रत्येक धातु की कितनी मात्रा नियत करता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम, अलौह धातुओं का नियतन करने वाला प्राधिकारी नहीं है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम सितम्बर, 1965 तक विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा किये गये राज्यवार नियतन के आधार पर विभिन्न राज्यों को अलौह धातुओं की पूर्ति करता रहा। विकास-आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा उत्तर प्रदेश को पिछले कुछ वर्षों में किये गये नियतन निम्न प्रकार थे :

इकाई : मेट्रिक टन

	1962-63	1963-64	1964-65
तांबा	2506	2527	1562
जस्ता	2000	1853	1103
सीसा	26	58.7	124
टीन	36	51.49	65.05
	(अक्तूबर 62 से मार्च, 63)		
अल्यूमीनियम तार की छड़ें			
अक्तूबर, 62-सितम्बर, 63			73
अक्तूबर, 63-मार्च, 64			122
1964-65			107
1965-66			66
निकल			
अप्रैल-सितम्बर, 63			38.65
अक्तूबर, 63-सितम्बर, 64			83.30
अक्तूबर, 64-मार्च, 65			35.375
1965-66			4.007

14 सितम्बर 1965 को भारत सरकार ने दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) आदेश, 1965 को प्रख्यापित किया जिस के अन्तर्गत तांबा, जस्त, सीसा तथा टीन जैसी अलौह धातुओं की खरीद तथा बिक्री को इस आदेश के अधीन नियुक्त किए गए नियंत्रक द्वारा जारी किए गए परमिटों से विनियमित किया गया और जून, 1965 तक कोई भी राज्यवार नियतन नहीं किया गया। नियतन आदेश को 7 जून, 1965 को रद्द किया गया था।

सरकार ने दिसम्बर, 1966 में लघु उद्योग क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं को सीधे ही आयात लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया। अतः आयात लाइसेंस सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को सीधे जारी कर दिये गये। किन्तु इस नीति को 1967-68 की अवधि के लिए परिवर्तित कर दिया गया और लघु उद्योग क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र दोनों प्रकार के गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों की आवश्यकताओं को, लाइसेंस देने वाले प्रधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले निकासी आदेशों के आधार पर पूरा करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उत्तरदायी बना दिया गया। राज्यों की इस प्रकार का कोई राज्यवार नियतन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नियतभागियों के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अब तक प्राप्त हुए निकासी आदेशों का कुल मूल्य निम्न प्रकार था :—

तांबा	5,03,687 रु०
जस्ता	2,45,536 रु०
टीन	1,98,308 रु०
सीसा	55,504 रु०
निकल	95,502 रु०
अल्यूमीनियम तार की छड़ें	12,668 रु०
प्रत्येक धातु के मूल्य का ब्यौरा दिये बिना किया गया नियतन	16,76,088 रु०